ई संदेश

19 मार्च, 2026 | अंक -197

सात दिन, सात पृष्ठ

भारत की राष्ट्रपति ने उ0प्र0 की राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में की 'श्रीराम यंत्र' की प्रतिष्ठापना

रसोई गैस (एल0पी0जी0) की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति हो, आमजन को सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए : मुख्यमंत्री

केन्द्रीय रक्षा मंत्री तथा उ0प्र0 के मुख्यमंत्री ने 'ग्रीन कॉरिडोर परियोजना' के कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को भेजी 900 करोड़ की राशि, माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेंगे समाज के सजग प्रहरियों के घर

ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से बदल रहा उत्तर प्रदेश: :मुख्यमंत्री ने सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को दिया सफलता का मंत्र

विरासत का सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को वितरित किए चेक

जल जीवन मिशन 2.0 का शंखनाद: केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच ऐतिहासिक जल-समझौता, अब हर गांव में पहुंचेगा शुद्ध जल

उत्तर प्रदेश बना वैश्विक निवेश का नया केंद्र: कनाडाई उच्चायुक्त ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट, तकनीक और कौशल विकास पर हुई विस्तृत चर्चा

झलकियां

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

भारत की राष्ट्रपति ने उ0प्र0 की राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में की 'श्रीराम यंत्र' की प्रतिष्ठापना

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में 19 मार्च, 2026 को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं सनातन नव संवत्सर (विक्रम संवत-2083) पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में श्रीराम यंत्र की प्रतिष्ठापना की तथा श्री रामलला का दर्शन-पूजन किया। इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर राष्ट्रपति ने देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और श्रीराम भक्तों को नव वर्ष तथा आगामी रामनवमी पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की इस पावन जन्मभूमि की धूलि का स्पर्श प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात है।

उन्होंने 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का स्मरण करते हुए बताया कि स्वयं प्रभु श्रीराम ने इस भूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की मूल प्रति के भाग-3 (मौलिक अधिकार) में अंकित प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी के अयोध्या आगमन के रेखाचित्र का विशेष उल्लेख करते हुए इसे संवैधानिक आदर्शों और सांस्कृतिक प्रतीकों के संगम का प्रतीक बताया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना' के रामराज्य वाले आदर्शों पर चलते हुए भारत वर्ष 2047 या उससे पूर्व ही एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में माता शबरी, निषादराज, माता अहिल्या और महर्षि वाल्मीकि जैसी महान विभूतियों की मूर्तियों के दर्शन कर इसे सर्व-समावेशी जीवन दर्शन का आधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांची कामकोटि पीठम द्वारा प्रदत्त 'श्रीराम यंत्र' की स्थापना भगवान शंकर और प्रभु श्रीराम के बीच प्रगाढ़ स्नेह और हमारी अटूट सनातन परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है।

इस गौरवशाली अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 'देव से देश' के दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा कि अयोध्या आज वैश्विक चेतना का केंद्र बन चुकी है, जहाँ आस्था अब राष्ट्रचेतना में परिवर्तित हो रही है। उन्होंने चंद्रयान, आदित्य मिशन और आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण देते हुए कहा कि समर्थ भारत का निर्माण नागरिकों के 'राष्ट्र प्रथम' के भाव से ही संभव है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने संबोधन में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के अंत और रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने को राष्ट्र मंदिर की पुनर्स्थापना बताया। मुख्यमंत्री ने विश्व में व्याप्त अशांति और आर्थिक अराजकता के बीच अयोध्या को भयमुक्त 'रामराज्य' की अनुभूति का केंद्र कहा और गौरव के साथ जानकारी दी कि वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 156 करोड़ श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा की है, जो नए और बदलते भारत की बदलती तस्वीर का जीवंत प्रमाण है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में दुनिया में अनेक जगह युद्ध चल रहे हैं। भय, अव्यवस्था व आर्थिक अराजकता है। हम भारत के अयोध्या धाम में भयमुक्त होकर राष्ट्रपति जी के सानिध्य में श्रीराम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में सहभागी बनकर रामराज्य की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे ऋषि-मुनियों की तपस्या, अन्नदाता किसानों के परिश्रम, कारीगरों की उद्यमिता तथा लोगों की आस्था ने भारत को सदैव 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाये रखा है। श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम से जुड़कर न केवल उत्तर प्रदेशवासी, बल्कि देश-दुनिया का प्रत्येक धर्मावलम्बी गौरव की अनुभूति कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रदेश में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए हैं। दुनिया के किसी भी देश की इतनी आबादी नहीं है। यह नया तथा बदलता हुआ भारत है। वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में जा रही है। आज युवा नया वर्ष मनाने के लिए मन्दिरों में जाता है। यही उसके संस्कार हैं।

रसोई गैस (एल0पी0जी0) की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति हो आमजन को सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 मार्च, 2026 को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ आहूत एक बैठक में प्रदेश में एल0पी0जी0 की वर्तमान माँग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में रसोई गैस (एल0पी0जी0) की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एल0पी0जी0 की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति न बनने दी जाए तथा आमजन को समय-समय पर सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर एल0पी0जी0 की कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने पाए। जिन उपभोक्ताओं ने एल0पी0जी0 की बुकिंग कराई है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध ढंग से रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उपभोक्ताओं को उनकी अगली रिफिल की सम्भावित तिथि के सम्बन्ध में भी समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, जितना कि अफवाहों के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। तेल कंपनियां प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एल0पी0जी0 की आपूर्ति और वितरण की वास्तविक स्थिति के बारे में आमजन को नियमित रूप से अवगत कराएं। केन्द्र सरकार भी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई वितरक एजेंसी अथवा निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर एल0पी0जी0 वितरक केन्द्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, ताकि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न बने और वितरण कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके।

अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा इनके वितरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विकल्प के रूप में प्रदेश को 80 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसे विकल्प के रूप में रखा जाए और आवश्यकता के अनुसार इसका यथोचित वितरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने छात्रावासों, धर्मशालाओं, अस्पतालों, होटलों तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संवाद स्थापित कर उन्हें वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए भी प्रेरित करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं रसद विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की स्थिति की सतत् निगरानी की जाए। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी तथा तेल कम्पनियों के स्थानीय प्रतिनिधि आपसी समन्वय से एल0पी0जी0 की समुचित आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित कराएं।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री तथा उ0प्र0 के मुख्यमंत्री ने 'ग्रीन कॉरिडोर परियोजना' के कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 13 मार्च, 2026 को यहां 1,519 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ के यातायात एवं अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने वाली 'ग्रीन कॉरिडोर परियोजना' के कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इनमें 299 करोड़ रुपये लागत से फेज-02 के कार्यों का लोकार्पण तथा 1,220 करोड़ रुपये लागत से फेज-03 व फेज-04 के कार्यों का शिलान्यास शामिल है। रक्षा मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी के समक्ष लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य एक एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज दुनिया में लखनऊ की चर्चा तहजीब के साथ-साथ उसके विकास के लिए भी हो रही है। यूनेस्को ने लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में मान्यता दी है। खान-पान के लिए प्रसिद्ध विश्व के श्रेष्ठ शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान मिलना हमारे लिए गौरव का विषय है। दुनिया के रहने लायक शहरों में लखनऊ का विशेष स्थान है। यह सभी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से सम्भव हुए हैं। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल ही में उनकी जापान और सिंगापुर की सफल यात्रा सम्पन्न हुई। वहाँ हुए निवेश समझौतों से उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अगर हम वहाँ के लोगों के अच्छे अनुभवों को उत्तर प्रदेश की मेहनत और क्षमता से जोड़ेंगे, तो परिणाम और अधिक बेहतर होंगे।

रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 28 किलोमीटर लम्बी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की लागत 07 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। यह ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ शहर के मध्य से गुजरते हुए शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय बचेगा और लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह परियोजना लखनऊवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस परियोजना में ग्रीनरी को व्यवस्थित करने का कार्य किया गया है। सड़क के रास्ते में आए पेड़ों को काटा नहीं गया है, बल्कि उन्हें दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया गया है। आई0आई0एम0 रोड से पक्का पुल तक बांध चौड़ीकरण के साथ-साथ फ्लाईओवर बन चुका है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। परियोजना के दूसरे चरण में डालीगंज पुल से समतामूलक चौक तक आज लखनऊवासियों को समर्पित 07 किलोमीटर लम्बे इस कॉरिडोर से 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। अगली कड़ी में समतामूलक चौक से शहीद पथ तक 10 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा।

इस परियोजना की विशेष बात यह है कि इसमें सिविल और डिफेंस सेक्टर दोनों ने मिलकर कार्य किया है। यह आपसी तालमेल इस बात का उदाहरण है कि जब सिविल और डिफेंस सेक्टर साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। लखनऊ में बाधारहित ट्रांसपोर्टेशन सम्भव हो सके, इस दृष्टि से यह ग्रीन कॉरिडोर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पूरी कोशिश रही है कि लखनऊ की मल्टीमोडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि लखनऊ बेहतरीन राजधानी के साथ सुगम यातायात का बेहतरीन केन्द्र बना है। देश व दुनिया के अतिथि आकर यहाँ की साफ-सफाई व नवाचार की सराहना करते हैं।

लोग कहते हैं कि लखनऊ ने कुछ नया करके दिखाया है। 'मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं', यह लखनऊ का प्रतीक बन चुका है। लखनऊ मेट्रो के कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने धनराशि स्वीकृत कर दी है तथा भारत सरकार के साथ मिलकर लखनऊ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं।

हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को धरातल पर उतारने का कार्य प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसा हो, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलतापूर्वक लोग अपने गन्तव्य तक कैसे पहुँचें, इसे ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। आज ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ वासियों के सुगम आवागमन के लिए समर्पित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2029-30 तक प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्बनाइजेशन इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। लखनऊ इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को तीव्र करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारम्भ किया है, आज वह 'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई राजधानी' के रूप में अपनी पहचान को आगे बढ़ा रही है। लखनऊ अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित हो रहा है। लखनऊ को ए0आई0 सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि की व्यवस्था कर दी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लखनऊ आगे है। यह देश की रक्षा आवश्यकताओं के नये केन्द्र के रूप में भी विकसित हुआ है। लखनऊ के विकास, कनेक्टिविटी, यहाँ निवेश की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने तथा इसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्री जी का जो भी मार्गदर्शन होगा, उसे प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज गल्फ क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। दुनिया में आर्थिक अराजकता की स्थिति है। सक्षम एवं योग्य नेतृत्व के कारण इन परिस्थितियों में भी हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। योग्य नेतृत्व में प्रत्येक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भारत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को भेजी 900 करोड़ की राशि, माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेंगे समाज के सजग प्रहरियों के घर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 मार्च, 2026 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' के अंतर्गत प्रदेश के 90 हजार लाभार्थियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके बैंक खातों में कुल 900 करोड़ रुपये की अनुदान राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की है। सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डी.बी.टी. (DBT) के जरिए प्रत्येक लाभार्थी को एक-एक लाख रुपये की प्रथम किस्त भेजी और विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर अब गरीबों के साथ-साथ अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक और पत्रकारों जैसे समूहों के लिए भी किफायती 'हाईराइज' बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि जहां कभी माफियाओं का डर था, वहां अब समाज के सजग प्रहरी अपना आशियाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 'हर व्यक्ति का अपना घर हो' के संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में बताया कि जनपद सहारनपुर में 10,214, प्रतापगढ़ में 7,991, शाहजहांपुर में 4,325, फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलन्दशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोण्डा में 1,121 लाभार्थियों सहित कुल 90 हजार लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त के रूप में कुल 900 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में प्रेषित की गयी है। अब कोई मध्यस्थ नहीं है। तकनीक के माध्यम से एक क्लिक में धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रही है।।

मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों को निर्माण में सुविधा देने के लिए प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं जो सस्ती दरों पर ईंट, बालू और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही, उन्होंने कहा कि जैसे ही मकान का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाए, तुरंत दूसरी किस्त की व्यवस्था की जाए ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। आवास के साथ-साथ शौचालय, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और नल से शुद्ध पेयजल की सुविधा देना भी अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को अपना परिवार मानकर बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में 2.09 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई थी और नए वित्तीय वर्ष में शेष पात्र लोगों को भी जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभ, पी.एम. स्वनिधि योजना और मेधावी बेटियों के लिए 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और रामनवमी की बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर परिणाम देती रहेगी और तकनीक के माध्यम से बिना किसी बिचौलिये के सीधे जनता तक लाभ पहुँचाती रहेगी।

ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से बदल रहा उत्तर प्रदेश: :मुख्यमंत्री ने सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को दिया सफलता का मंत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 मार्च, 2026 को लखनऊ में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'नेशनल सिक्योरिटी एण्ड स्ट्रेटजिक स्टडी' कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों से विशेष संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बल, भारत सरकार की सिविल सेवाओं और विभिन्न मित्र देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में 'ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी' उत्तर प्रदेश के व्यापक परिवर्तन के दो प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उभरे हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ प्रदेश की प्रगति का विवरण देते हुए बताया कि पिछले 09 वर्षों की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है और आज उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक हाई-वे व एक्सप्रेस-वे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है, जहाँ अकेले देश के लगभग 55 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। वर्ष 2017 से पूर्व की स्थितियों का स्मरण कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तब प्रदेश में सुरक्षा एक अत्यंत गंभीर चुनौती थी, किंतु सरकार ने 'रूल ऑफ लॉ' (कानून का शासन) स्थापित कर अवैध वसूली और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण पाया है, जिससे न केवल निवेश का वातावरण बना है बल्कि विकास को भी अभूतपूर्व गति मिली है।

मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के तीव्र विकास पर विशेष बल दिया और बताया कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई एक एंकर यूनिट के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो भविष्य में अनेक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए अपार अवसर सृजित करेगी। उन्होंने कानपुर नोड में आए बड़े निवेश और हरदोई की वेब्ले स्कॉट उत्पादन इकाई का उल्लेख करते हुए सैन्य अधिकारियों को कॉरिडोर का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अवस्थापना सुविधाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने जेवर में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और लगभग पूर्ण हो चुके गंगा एक्सप्रेस-वे की प्रगति से अवगत कराया। सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रदेश के प्रत्येक मंडल में साइबर फोरेंसिक लैब, हर जिले में फोरेंसिक मोबाइल वैन और सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया।

पारदर्शिता के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डी.बी.टी. व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं का लाभ अब बिना किसी बिचौलिये के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। प्रदेश की लगभग 80 हजार उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के जरिए राशन वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, साथ ही 01 करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की पेंशन सीधे उनके खातों में प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 62 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिए जा चुके हैं और इसी क्रम में 16 मार्च को ही 90 हजार नए लाभार्थियों को भी योजना से जोड़ा गया है। नीतियों के क्रियान्वयन पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही को सफलता का मंत्र बताया। उन्होंने अपनी सिंगापुर और जापान यात्राओं के संस्मरण साझा करते हुए जापान के नागरिक अनुशासन और स्वच्छता की सराहना की और वहां के उद्योग जगत द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति दिखाई गई रुचि की जानकारी दी। एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका, मंगोलिया, मालदीव, आर्मेनिया और ब्राजील जैसे देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल थे।

विरासत का सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को वितरित किए चेक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 मार्च, 2026 को लोक भवन सभागार, लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले प्रदेश के 555 श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति एक-एक लाख रुपये की अनुदान राशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राचीन काल से ही भारतीय सनातन धर्म की परंपरा और राष्ट्र की एकात्मता को सशक्त करने का माध्यम रही है। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि आदि शंकराचार्य ने जिस सांस्कृतिक भाव से पूरे भारत को जोड़ा था, आज वर्तमान सरकार उसी दायित्व का निर्वहन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साहस की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान आने वाली कठिन चुनौतियों और आपदाओं के बावजूद देवाधिदेव महादेव के प्रति अटूट आस्था हमेशा भारी पड़ती है। प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और इसी क्रम में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया गया है, जिसका उपयोग अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक पर्यटन की मर्यादा पर जोर देते हुए कहा कि तीर्थाटन में श्रद्धा भाव सर्वोपरि होना चाहिए, जिससे हम अपने पवित्र स्थलों की गरिमा और पवित्रता को बनाए रख सकें। उन्होंने वर्ष 2025 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर रिकॉर्ड 164 करोड़ श्रद्धालु आए, जिनमें से अकेले प्रयागराज महाकुंभ-2025 में 66 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम और मथुरा-वृंदावन जैसे केंद्रों पर बढ़ती भीड़ को सरकार एक अवसर के रूप में देख रही है, जिससे विकास और रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने काशी-तमिल संगमम् का उदाहरण दिया और कहा कि उत्तर-दक्षिण को जोड़ने के प्रयासों के तहत अब काशी से रामेश्वरम की यात्रा को और सुगम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य विभाग को निर्देश दिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल नवाचारों और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए, ताकि प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्राप्त हो।

जल जीवन मिशन 2.0 का शंखनाद: केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच ऐतिहासिक जल-समझौता, अब हर गांव में पहुंचेगा शुद्ध जल

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से बुधवार, 18 मार्च 2026 को एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) 2.0 के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर वर्चुअल माध्यम से हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय कैबिनेट से हाल ही में मिली मंजूरी के बाद यह समझौता मिशन के अगले चरण की औपचारिक शुरुआत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'हर घर नल से जल' के संकल्प को जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह समझौता जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर नियोजन, समयबद्धता और परिणामों को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस मिशन के माध्यम से न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शुद्ध पानी पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकेगा।

प्रदेश में आए बदलावों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पाइप पेयजल के लिए तरसने वाले हजारों गांवों में आज नियमित जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाने में स्वच्छ पेयजल की भूमिका को अहम बताया और कहा कि बुंदेलखंड व विंध्य जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों में आज घर-घर नल पहुंच चुका है। सरकार का ध्यान अब केवल कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन और सुदृढ़ रखरखाव पर भी है ताकि यह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ बनी रहे।

वहीं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील ने गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य टिकाऊ होने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता न केवल पेयजल व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

उत्तर प्रदेश बना वैश्विक निवेश का नया केंद्र: कनाडाई उच्चायुक्त ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट, तकनीक और कौशल विकास पर हुई विस्तृत चर्चा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में कनाडा के उच्चायुक्त श्री क्रिस्टोफर कूटर के बीच 18 मार्च, 2026 को उनके सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी को लेकर विस्तृत रोडमैप पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य की बदलती आर्थिक तस्वीर और भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

उच्चायुक्त श्री क्रिस्टोफर कूटर ने भारत और कनाडा के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की संभावनाओं पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश और नवाचार के एक उभरते हुए 'ग्लोबल हब' के रूप में रेखांकित किया।

शिक्षा और अनुसंधान को इस साझेदारी का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग से न केवल कौशल विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि वैश्विक प्रतिभा विनिमय और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कनाडाई कंपनियां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के अवसरों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रही हैं।

उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक बदलावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ नेतृत्व की सराहना की। श्री कूटर ने विशेष रूप से प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना (Infrastructure), दूरदर्शी नीतिगत सुधारों और बेहतर सुशासन (Governance) की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने उत्तर प्रदेश को दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक अत्यंत विश्वसनीय और आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

भेंट के दौरान कनाडाई उच्चायुक्त ने उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी, एल.एन.जी./एल.पी.जी., क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing) जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उपलब्ध निवेश-अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हुए कनाडाई कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी रणनीतिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की बढ़ती विनिर्माण क्षमता को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए एक पारदर्शी, स्थिर और उद्योग-अनुकूल नीतिगत ढांचा सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कनाडा के साथ तकनीकी सहयोग और नवाचार को गति देने के लिए राज्य सरकार हर संभव संस्थागत समर्थन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर इस साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

अयोध्या में श्री राम यंत्र स्थापना की झलकियां

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित